

#### प्रपत्र-4

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी०)

#### संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 21-03-2014 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार रॉय, उपराजिक, राजस्व विभाग की ओर से श्री महेश चन्द्र, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री हरीश सिंह नेगी (कनिष्ठ अभियन्ता) द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि, शून्य हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.035 हे०, वन पंचायत भूमि 0.1575 हे० एवं नाप भूमि 2.1825 हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग, 304 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 47 वृक्षों व नाप भूमि पर 40 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

तहायक आभय-ता.  
वर्माण खण्ड लो/नि. विभाग  
खण्डाट (पिथौरागढ़)  
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

अधिसारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो/नि. विभाग  
खण्डाट (पिथौरागढ़)  
ह०/-  
(राजस्व विभाग का  
प्रतिनिधि)  
कनालीखेना पिथौरागढ़

ह०/-  
(वन विभाग का प्रतिनिधि)

ह०/-  
(जिला अधिकारी)

ह०/-  
प्रभागीय वन अधिकारी  
(प्रभागीय वन अधिकारी)  
पिथौरागढ़

वन क्षेत्र अधिकारी  
जैडीहाट वन क्षेत्र

उप नि. अधिकारी  
ह०/-  
(सम्बन्धित उप नि. अधिकारी)  
जनपद-पिथौरागढ़  
(उत्तराखण्ड)

ह०/-  
तहसीलदार  
कनालीखेना (पिथौरागढ़)  
15/04/2015



प्रपत्र-5

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF  
(for the forest land to be diverted under FCA)**

5.1 A proposal has been received by this office from E.E PWD Askote for diversion under FCA-1980) of 1.1925 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Kathpativa-Gudoli To Doula Motor road. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated.....

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring .....1.1925..... ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. *yes*

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- *NO*

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

*NOT Required*

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. ✓

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. *Hence Perbasal is recommended for acceptance*

(Signature)

Place:- *Pithoragarh*

Name.....

Date.....

Designation. *प्रभागीय वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़*

N.B.

Office Seal .....

x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.